भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1655
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2015 को दिया जाना है

'मेक इन इंडिया' के विस्तार हेतु कार्य योजना

1655. श्री प्रेम चन्द गुप्ता:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 'मेक-इन-इंडिया' एवं 'मेड-इन-इंडिया' के विस्तार हेतु कार्य योजना बना ली गई है/बनाई जा रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या रेलवे जैसे अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के अधीन होने वाले निर्माण, विनिर्माण एवं उत्पादन के लिए सरकार ने कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): सरकार ने भारत को विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए डिजाइन किए गए एक प्रमुख नए राष्ट्रीय कार्यक्रम, 'मेक इन इंडिया' की शुरूआत की है जिसमें निम्नलिखित चार प्रमुख विषय शामिल हैं:

I. **नई प्रक्रियाएं** :'मेक इन इंडिया' में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक के रूप में 'व्यवसाय करने में सरलता' की पहचान की है। व्यवसाय हेतु वातावरण में सुधार के लिए पहले ही अनेक उपाय प्रारंभ किए जा चुके हैं।

II. **नई अवसंरचना**: सरकार औद्योगिक कोरिडोर और स्मार्ट शहर, अद्यतन प्रौद्योगिकी सहित विश्वस्तरीय अवसंरचना तथा हाई स्पीड कम्युनिकेशन भी विकसित कर रही है। एक त्वरित गति की आईपीआर पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से नवाचार और अनुसंधान कार्यकलापों को समर्थन दिया गया है।

III. **नए सेक्टर**: रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा डिवाइस, निर्माण और रेलवे अवसंरचना के लिए एफडीआई को उदार बनाया गया है।

IV. **नए विचार**: देश के आर्थिक विकास में उद्योग के साथ साझेदारी के लिए, सरकार केवल विनियामक के रूप में ही नहीं बल्कि मददकर्ता के रूप में भी कार्य करेगी।

(ख): जी, नहीं। भारी उद्योग विभाग ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

*****